एमएसएमई : नवाचार और विकास की नई रीढ़

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 30 लाख को लाभ

80 लाख नौकरियां, 9.87 लाख इकाइयां स्थापित

6.3 करोड़ एमएसएमई अर्थव्यवस्था में दे रहे योगदान

नई दिल्ली, 27 जून. एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाने वाला, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा नवाचार, रोजगार और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है.

स्थानीय कारीगरों से लेकर उभरते तकनीकी स्टार्टअप तक, एमएसएमई मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं. यह दिन उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों को उजागर करता है, जबकि एक तेजी से प्रतिस्पर्धी दुनिया में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए नीतिगत समर्थन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में नामित यह दिन, विशेष रूप से महामारी के बाद की, डिजिटल रूप से विकसित दुनिया में - लचीलेपन और विकास के इंजन के रूप में छोटे व्यवसायों का समर्थन और सशक्तिकरण के महत्व की याद दिलाता है.संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एमएसएमई सभी व्यवसायों का 90त्न हिस्सा हैं, 60-70त्न रोजगार में योगदान करते हैं, और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधा हिस्सा उत्पन्न करते हैं. भारत में, इस क्षेत्र का और भी अधिक महत्व है - यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और निर्यात में 45% का योगदान देता है, और रोजगार सृजन में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है.इस वर्ष, एमएसएमई मंत्रालय %उद्यमी भारत - एमएसएमई दिवस% मना रहा है. 2025 के लिए विषय स्थायी विकास और नवाचार के चालकों के रूप में एमएसएमई की भूमिका बढ़ाना पर केंद्रित है.

प्रमुख सरकारी योजनाएं

मंत्रालय ने बताया कि भारत 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई का घर है, जो विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं तक फैले हुए हैं .इस क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख पहलें चल रही हैं .सितंबर 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है. 26 जून, 2025 तक, इस योजना के तहत 2.71 करोड़ से अधिक आवेदन जमा किए गए थे, जिसमें लगभग 30 लाख लाभार्थी पंजीकृत थे.

विदेशी मुद्रा भंडार 1.02 अरब डॉलर घटकर 697.19 अरब डॉलर पर

मुंबई, 27 जून (वार्ता) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास आरक्षित निधि में भारी गिरावट होने से 20 जून को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.02 अरब डॉलर कम होकर 697.19 अरब डॉलर पर आ गया.वहीं, इसके पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी लेकर 698.9 अरब डॉलर पर रहा था.रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार, 20 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 35.7 करोड़ डॉलर की गिरावट लेकर 589.1 अरब डॉलर पर आ गई.

मेड इन इंडिया होगा मजबूत : गोयल

क्यूसीओ से एमएसएमई की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी

नई दिल्ली,27 जून.केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर लाभ पहुंचाया है.

क्यूसीओ घटिया उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि उन्होंने क्यूसीओ के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के साथ एक हितधारक परामर्श बैठक की.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रॉसेस को अधिक सहयोगात्मक, समावेशी और अनुपालन में आसान बनाने पर उनकी प्रतिक्रिया की सराहना की. एमएसएमई ने स्वीकार किया कि क्यूसीओ ने उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतोष को बढ़ाकर उनके क्षेत्र को लाभ पहुंचाया है.

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' के दृष्टिकोण के अनुरूप, एमएसएमई ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 'क्वालिटी माइंडसेट' के महत्व को भी दोहराया.उद्योगों में एक मजबूत क्वालिटी फ्रेमवर्क स्थापित करने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, डीपीआईआईटी विनिर्माण मानकों को बढ़ाने और 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए क्यूसीओ को सक्रिय रूप से अधिसूचित कर रहा है. इन प्रयासों को टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट मैनुअल और परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता के विकास द्वारा पूरक किया जाता है.

इन पहलों के माध्यम से, सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के तहत एक विश्व स्तरीय, आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है.

क्यूसीओ से एमएसएमई की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ीक्यूसीओ भारत में उत्पाद मानकों को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाते हैं, जिससे भारतीय निर्माता घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में आगे बढ़ सकें .इस महीने की शुरुआत में, देश में मान्यता के राष्ट्रीय संरक्षक, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएल) का एक नया पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और विशेष रूप से प्रयोगशालाओं और एमएसएमई के लिए डिजिटल पहुंच को बढ़ाना है .

सेंसेक्स ने रचा नया इतिहास हुआ 84,000 के पार

नई दिल्ली,27 जून. कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 83,774.45 अंक पर खुला लेकिन बिकवाली होने से थोड़ी देर बाद ही 83,645.41 अंक के निचले स्तर पर आ गया. वहीं, लिवाली होने से कारोबार के अंतिम चरण में यह 84,089.35 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. अंत में पिछले दिवस के 83,755.87 के मुकाबले 0.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकर 84058.90 अंक हो गया.

इसी तरह निफ्टी भी 28 अंक की तेजी के साथ 25,576.65 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 25,523.55 अंक के निचले जबकि 25,654.20 अंक के निचले स्तर पर रहा. अंत में पिछले सत्र के 25,549.00 अंक की तुलना में 0.35 प्रतिशत मजबूत होकर 25,637.80 अंक पर बंद हुआ.

इस दौरान सेंसेक्स की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में एशियन पेंट 3.06, अल्ट्रासिम्को 2.43, पावरग्रिड 2.11, आईसीआईसीआई बैंक 1.56, रिलायंस 1.39, बीईएल 1.19, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.14, सन फार्मा 1.12, एसबीआई 1.05, अदानी पोर्ट्स 0.75, टाटा स्टील 0.56, टाटा मोटर्स 0.54, एलटी 0.50, भारती एयरटेल 0.38, एनटीपीसी 0.24, कोटक बैंक 0.18, एचसीएल टेक 0.08 और टीसीएस 0.04 प्रतिशत शामिल रही.

खाद्य तेलों में टिकाव

नई दिल्ली 27 जून (वार्ता) विदेशी बाजारों में तेजी लौटने के बावजूद स्थानीय स्तर पर उठाव सुस्त रहने से आज दिल्ली थोक जिंस बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा जबकि दालों में मिलाजुला रुख रहा वहीं अन्य जिंसों के भाव स्थिर रहे.

तेल-तिलहन- वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का जुलाई वायदा 53 रिंगिट बढ़कर 3992 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया. इसी तरह जुलाई का अमेरिकी सोया तेल वायदा 0.14 सेंट की तेजी के साथ 52.67 सेंट प्रति पौंड बोला गया.

इस दौरान घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में टिकाव रहा. सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल, सोया रिफाइंड, पाम ऑयल और वनस्पति तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

ऋषिकेश कुमार को मिला सीएमए अवार्ड

एनबीसीसी निदेशक को मिला श्रेष्ठ सीएमए पुरस्कार

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने किया सम्मानित

नई दिल्ली,27 जून, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक (वित्त) ऋषिकेश कुमार को सोमवार को प्रतिष्ठित बेस्ट सीएमए अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह सम्मान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 19वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट और 8वें सीएमए अवार्ड 2024 समारोह में प्रदान किया गया.

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय संसद सदस्य एवं वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने ऋषिकेश कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया.

एनबीसीसी अपनी कार्यसंस्कृति पर गर्व करता है, जो अपने प्रतिभाशाली कार्यबल की पेशेवर वृद्धि को बढ़ावा देती है. कंपनी में वित्तीय कार्यप्रणाली का नेतृत्व अनुभवी पेशेवरों द्वारा किया जाता है, जिनमें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (सीएमए) शामिल हैं. वित्तीय पेशेवरों की कुल संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक सीएमए हैं, जो लेखांकन, फंड प्रबंधन, कराधान और अन्य विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

2026 की तीसरी तिमाही में उछलेगा बाजार

आरबीआई का नरम रुख बाजार को देगा सहारा : मॉर्गन स्टेनली

कम ब्याज दरें ऋण और निवेश को बढ़ाएंगी

मुंबई,27 जून.वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय शेयर बाजार वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में बढ़ने की अधिक संभावना है.

फर्म भारतीय इक्विटी को लेकर तेजी का रुख बनाए हुए है, उनका मानना है कि मजबूत विकास के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक कदम और उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट आय जुलाई से बाजार को ऊपर धकेलेंगे.

मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, भारत में लगातार सुधार के संकेत दिख रहे हैं. सरकारी खर्च बढ़ रहा है, और आरबीआई अधिक सहायक या नरम नीतिगत रुख की ओर बढ़ रहा है. यह, घटती मुद्रास्फीति के साथ मिलकर, शेयर बाजार के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है.ब्रोकरेज का यह भी मानना है कि कम ब्याज दरें बैंकों को अधिक ऋण देने में मदद करेंगी, जिससे ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा. इसके अतिरिक्त, यदि वैश्विक अनिश्चितताएं कम होती हैं, तो भारतीय कंपनियां नए परियोजनाओं में अधिक निवेश करना शुरू कर सकती हैं.आगामी कॉर्पोरेट आय का मौसम एक महत्वपूर्ण ट्रिगर हो सकता है. मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि कम आधार, बेहतर दक्षता स्थर उपभोक्ता मांग के कारण कई कंपनियां बाजार की उम्मीदों को पार करेंगी.

पठानकोट से कतर को भेजी गई सेंटेड लीची

नई दिल्ली,27 जून.भारत ने कतर के लिए गुलाब की खुशबू वाली सेंटेड लीची भेजी है. जी हां, भारत के बागवानी निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए पठानकोट से कतर के लिए सेंटेड लीची की पहली खेप रवाना की जा चुकी है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बागवानी विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंजाब सरकार के सहयोग से 23 जून 2025 को पंजाब के पठानकोट से कतर के दोहा के लिए 1 मीट्रिक टन गुलाब की खुशबू वाली सेंटेड लीची की पहली खेप को रवाना किया.इसके अलावा, पठानकोट से दुबई को 0.5 मीट्रिक टन लीची का निर्यात भी किया गया,

जियो ब्लैकरॉक को ब्रोकिंग की मंजूरी

सेबी ने ब्रोकिंग लाइसेंस को दी हरी झंडी

अब निवेशकों को मिलेगा पूरा समाधान पैकेज

मुंबई, 27 जून.भारत के वित्तीय बाजार में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए, जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से ब्रोकरेज फर्म के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है.

जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियोब्लैकरॉक ब्रोकिंग का लक्ष्य भारतीय निवेशकों के लिए किफायती, पारदर्शी और तकनीक-आधारित निष्पादन क्षमताएं लाना है.यह जियो ब्लैकरॉक संयुक्त उद्यम के लिए तीसरी नियामक मंजूरी है. इससे पहले, जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को म्यूचुअल फंड बाजार में उतरने और निवेश सलाहकार के रूप में काम शुरू करने की अनुमति मिली थी.

जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ मार्क पिलग्रेम ने कहा कि इस मंजूरी से वे बेहद खुश हैं और इससे भारत को बचतकर्ताओं के देश से निवेशकों के देश में बदलने में मदद मिलेगी .उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत सलाह और एक मजबूत एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म दोनों मिलेंगे .

समाचार विशेष

मराठी अस्मिता का सवाल या 'राज' की नई चाल?

भाषा विवाद पर क्यों पलट गए फडणवीस

मुंबई. महाराष्ट्र में इस समय स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर बवाल मचा हुआ है. राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में हिंदी को मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने का आदेश जारी किया है. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ये विवाद ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की आहट है.

विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपने पिछले आदेश को पलटते हुए एक नया आदेश निकाला. जिसमें कहा हिंदी के लिए अनिवार्य शब्द को हटा दिया गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार ने इस समय अपना ही फैसला क्यों पलटा. साथ ही निकाय चुनाव पर क्या पड़ेगा असर?

बता दें कुछ समय पहले सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में अनिवार्य करने का फैसला सुनाया था, हालांकि, विपक्षी दलों और मराठी भाषा समर्थकों के विरोध के कारण सरकार ने तब ये फैसला वापस ले लिया था लेकिन अब कुछ संशोधन के साथ इसे जारी किया है. फडणवीस सरकार ने हिंदी विषय पढ़ाए जाने से अनिवार्यता शब्द हटा दिया है, बावजूद इसके विपक्षी दल स्कूलों में हिंदी को थोपे जाने का कदम बताया है. मराठी बनाम गैर मराठी के मुद्दें पर राजनीति शुरू हो गई है. इस मुद्दे के जरिए निकाय चुनाव में मराठी वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद तेज हो गई है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने इस आदेश का विरोध करके मराठी भाषी लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है. मराठियों का झंडा उठाने वाली मनसे ने हिंदी किताबों के पहले और आखिरी पन्ने जला दिए और किताबें फाड़ भी दीं.

इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन द्विवेदी का कहना है कि हिंदी भाषा को लेकर अनिवार्य शब्द हटाने के पीछे राज ठाकरे हो सकते हैं. यह किसी से छिपा नहीं है कि राज ठाकरे ने लोकसभा में बिन शर्त भाजपा का समर्थन किया था.

निकाय चुनाव में भाजपा पर क्या पड़ेगा असर?

भाजपा इस मुद्दे को लेकर काफी सतर्क है .पिछली बार जब भाजपा ने स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया था, तो उसे डर था कि इसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा के विरोध के तौर पर देखा जा सकता है, इसलिए भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति सरकार ने विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया था .लेकिन अब नए फैसले में अनिवार्य शब्द को हटाकर भाजपा ने मराठी लोगों की नाराजगी दूर करने और महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों का दिल जीतने की चाल चली है .

केजरीवाल नहीं सिसोदिया जाएंगे राज्यसभा

नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और गुजरात की विसावदर सीट पर जीत ने पार्टी के अंदर उत्साह का संचार कर दिया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाए रखने वाले केजरीवाल इसके बाद खुद कैमरे के सामने आए और इस जीत पर प्रत्याशियों को बधाई दी, लेकिन इस जीत के बीच एक पेंच फंसा हुआ है और वो है राज्यसभा सीट.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे. पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली सीट बचाना मुश्किल हो गया था. इस हार ने केजरीवाल के साथ-साथ उनके साथी दिग्गज नेताओं के चुनावी भविष्य को भी खतरे में डाल दिया था. केजरीवाल और उनकी पार्टी को उसी दिल्ली में ऐसी हार का सामना करना पड़ा, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक दौर की शुरुआत की थी.

क्यों शुरू हुई राज्यसभा जाने की चर्चा?- जब राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने लुधियाना उपचुनाव में जीत दर्ज की तो राजनैतिक गलियारों में चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल अब संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जाएंगे. लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है, तो अब खुद आप के अंदर ही इसको लेकर कई राय हैं.

कालीगंज का नतीजा क्या कहता है?

कोलकाता. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीत गई हैं. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आशीष घोष को 50 हजार वोट से हराया. कांग्रेस के उम्मीदवार काबिलउद्दीन शेख को 28 हजार वोट मिला.

कांग्रेस उम्मीदवार को सीपीएम ने समर्थन दिया था. कालीगंज सीट तृणमूल कांग्रेस के विधायक के निधन से खाली हुई थी और पार्टी ने उनकी बेटी को उम्मीदवार बनाया था, जो जीती हैं. पिछली बार यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को लगभग इतने ही वोट मिले थे. भाजपा का दावा है कि उसे हिंदुओं के 70 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं. अगर ऐसा है तो यह तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता की बात होगी.

ध्यान रहे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30 फीसदी के करीब है और हिंदू आबादी 70 फीसदी के करीब है. अगर हिंदू आबादी को 50 या 60 फीसदी वोट भी भाजपा को मिल जाए तो वह जीत की गारंटी नहीं है क्योंकि हिंदू वोट का 50 फीसदी हिस्सा भी कुल वोट का सिर्फ 35 फीसदी होगा.

विशेष | **कांग्रेस ने ठोका दावा ; क्या करेगी आरजेडी?**

2 चर्चित सीटों पर गरमाई सियासत

भागलपुर. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट के बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है. एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने-सामने की लड़ाई तय मानी जा रही है. दोनों गठबंधन में सीटों का पेच सुलझाने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. हाल ही में दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में जिला इकाई ने भागलपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में से चार पर दावेदारी पेश कर दी है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल का कहना है कि कांग्रेस ने भागलपुर विधानसभा को अपनी सीटिंग सीट मानते हुए इस पर दावा ठोका है. जहां से वर्तमान विधायक अजीत शर्मा हैं. इसके अलावा सुल्तानगंज और कहलगांव

विधानसभा सीटें, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं. यह दोनों सीटें पार्टी की प्राथमिकता में शामिल हैं. अब कांग्रेस ने नवगछिया अनुमंडल के बिहपुर व गोपालपुर विधानसभा में से किसी एक पर दावा जता दिया है.

पार्टी नेताओं का कहना है कि इन इलाकों में अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है. जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को लाभ मिल सकता है. कांग्रेस ने माई बहिन योजना के तहत महिलाओं के लिए 2,500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद देने का वादा किया है. इस योजना के लिए पार्टी गांव-गांव शिविर लगाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है. बीते 20 दिनों में ही 30 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं. कांग्रेस के नेता इस योजना को पार्टी का मास्टरस्ट्रोक मान रहे हैं.

उधर, एनडीए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए मासिक सहायता राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने की घोषणा की है. दोनों गठबंधनों की इस कवायद से साफ है कि चुनाव में सामाजिक योजनाएं और आर्थिक मदद बड़े मुद्दे बनेंगी.

अरविंद केजरीवाल ने किया साफ इनकार

दरअसल, लुधियाना पश्चिम सीट से उपचुनाव में आप की तरफ से संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे थे .पंजाब में सत्ता का फायदा आप को मिला और संजीव अरोड़ा विजयी साबित हुए .चूंकि संजीव अरोड़ा अब सांसद नहीं बल्कि विधायक होंगे, इसलिए कयास लगाए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के नाम का ऐलान होगा, लेकिन केजरीवाल ने कैमरे के सामने साफ इनकार कर दिया .